

under suspension, following the accident, pending detailed enquiry.

Immediate steps have been initiated to brother intensify safety procedures broaghou; the plant. The production in the Steel Melting Shop resumed at 1640 hours on 23-7-94.- Situation in the plant is normal. The Trade Loions as, well as Officer's Association, are co-operating in maintaining peace and normalcy.

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI): There is one name for seeking clarifications—Shri Ram Gopal Yadav. He is not present in the House. So, we will go to the next item

Now, clarifications on the Statement made by the Minister regarding the flood situation in the country. Now, Shri S. K. T. Ramachandran to seek clarifications. We have other names also from the Members of the Opposition who are not in the House now.

CLARIFICATIONS ON THE STATEMENT BY MINISTER

Flood situation in the country

SHRI S. K. T. RAMACHANDRAN (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, natural calamities in the form of floods and in other ways have become a periodical occurrence. So, the aftermath of these calamities are huge losses in the form of human deaths-and also losses of properties and damages to the infra structure and so on. As this is a regular occurrence, the Government should give serious thought to the ques tion of constituting a revolving fund to meet emergency requirements. Last time also, we insisted on this. At that time, the Minister assured us that the Government would give some thought to it. But so far as I know, no step has been taken to constitute such a revolving fund which would enable us to take up relief operations immedi ately.

Sir, we are having the data in regard to rains for the last sixty or hundred

years. We have data concerning' rains, wind direction, wind speed, etc. The question is whether, with all this data available with us, we could take up research to anticipate such calamities. Of course, I do not think it is very easy.. because, here we are up against the mighty Nature. Though wo are in a small planet, namely, Earth, the Eartbr is being acted upon by forces from she far-off stars. Therefore, it is . not easy to anticipate, such calamities on the basis of the data we have. Though it seems to me that it is unpredictable, at least, to some extent, such research would help us. I would like to know from the hon. Minister whether they have any such research centres

To sum up, I would like to know, firstly, what steps the Government has taken in regard to setting up a revolving fund to meet such calamities, Secondly, I would like to know whether there is any research centre existing already for the purpose of analysing the data relating to rains, wind and such things so that we could foresee or predict a natural calamity.

Thank you.

श्री सल चन्द मोषा (राजस्थान) : सम्भाषित महोदय, पिछले हफ्ते मंत्री जी ने बाढ़ पीड़ितों के संबंध में अपना वक्तव्य दिया । जब कभी भी वर्षाकालीन ऋतु आती है तो हिन्दुस्तान का इतिहास रहा है कि कहीं न कहीं, किसी न किसी प्रदेश के अन्दर बाढ़ जरूर आती है । आजादी के 47-48 साल होने के बावजूद भी हम इस देश के अन्दर ऐसी व्यवस्था नहीं कर पाये कि बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा से देश के लोगों को बचाया जा सके, उसको सुरक्षा दी जा सके । अब की बार प्रधानमंत्री जी को हमें बधाई देनी चाहिये, धन्यवाद देना चाहिये कि उन्होंने बाढ़ पीड़ित, बाढ़ से होने वाली मृत्यु या बाढ़ से होने वाले नुकसान के लिये एकट्ठा अनुदान देने की इस ब़ार घोषणा की है, इसके लिये तो हमें प्रधानमंत्री श्री नरसिंह राव जी को बधाई देनी चाहिये । लेकिन यह जो

वर्षा का अनुमान मौसम विभाग का है, इसके जितने भी अनुमान अब तक आये हैं, उनका उल्टा परिणाम निकला है। स्थिति यह होती है कि जिस एरिया में गत वर्ष बाढ़ आई, अब की बार वह एरिया खेज हो गया, उसमें परिवर्तन हो गया। जैसे यूपी० और बिहार का बाँधर नदी में बाढ़ आने से हर बार बढ़ता रहता है तो कुदरत की देन ऐसी है कि बाढ़ की समस्या भी बदलती रहती है। जिस एरिया में बाढ़ आती है उस एरिया में नहीं आई और जिस एरिया में सूखा पड़ता है उसमें बाढ़ आई। उदाहरण के तौर पर राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, सिरोही, जालीर जिलों में जहाँ सूखा एरिया माना जाता है उसमें गत वर्ष और इस साल भी भयंकर बाढ़ आई जिससे कई लोगों की जानें गईं। जब हम यह सोचते थे कि राजस्थान के पूर्वी और दक्षिणी एरिया में ज्यादा वर्षा हुआ करती है, वहाँ बाढ़ के इलाज के लिये ऐसे साधनों का उपयोग किया गया जिससे बाढ़ से लोगों को बचाया जा सके, लेकिन दुर्भाग्य है, प्रकृति की देन है कि जिस एरिया में सुरक्षा की व्यवस्था की गई वहाँ बाढ़ नहीं आई और जिस एरिया में सूखा पड़ता था वहाँ बाढ़ आ गई। तो मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि हिन्दुस्तान के कोने-कोने में सुरक्षा के लिये क्या उपाय किये गये हैं जिससे कि लोगों को बाढ़ से बचाया जा सके।

श्रीमन्, इस वर्ष विशेष रूप से यह बात सामने आई है कि इस वर्ष ज्यादा वर्षा हुई है जैसा कि आपने अपने वक्तव्य में भी कहा है। तो मंत्री जी यह बताने की कृपा करें कि पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा के कौन कौन से एरिये हैं जो पहले कभी बाढ़ की चपेट में नहीं आये हैं और अब की बार उनमें बाढ़ आई है। कितने लोगों की जानें गई हैं, कितने माल की हानि हुई है मानसून सीजन के अन्दर

कुल कितने लोगों की जानें गई हैं।

श्रीमन्, कुछ राज्यों से बाढ़ पीड़ित लोगों के बारे में जो स्थिति का जायजा लेना था उनकी रिपोर्टें नहीं आई हैं। इसके पीछे उन राज्यों से रिपोर्टें नहीं आने का क्या कारण है वह भी बताने की कृपा करें। आपने अपने केन्द्रीय राहत आयुक्त की एक समिति बनाई है। वह राज्य जहाँ से रिपोर्टें नहीं आई हैं क्या राहत में बाहर हो गये हैं या बाढ़ की समीक्षा बाद में करने के बाद उसी तरह से उन राज्यों को भी अनुदान मिलेगा, यह भी बतायें।

श्रीमन्, मंत्री जी के वक्तव्य के अनुसार बाढ़ पीड़ित लोगों के लिये भोजन की व्यवस्था, अनिवार्य वस्तुओं की सप्लाई और खाने पीने तथा दवाइयों का इंतजाम किया गया है। साथ ही बाढ़ आने के बाद उस एरिया में जो अनेक प्रकार की बीमारियाँ फैलती हैं इन बीमारियों से पीड़ित लोगों के इलाज के लिये आपने जो बताया कि उनको दवाइयाँ उपलब्ध करा रहे हैं, ये बहुत कम है। क्या बाढ़ आने के एक महीने बाद उस एरिया के अन्दर जो कोड़े, मकोड़े भण्डार पैदा होकर भयंकर बीमारियाँ पैदा कर देते हैं उस एरिया में रहने वाले लोगों की स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिये क्या आपने वहाँ पर परमेनेंट साल भर के लिये कोई चिकित्सकों की व्यवस्था की है या करेंगे जिससे उनको मुफ्त में दवाइयाँ मिल सकें और उनको रक्षा की जा सके।

इतने ही मेरे सवाल हैं जिनका उत्तर मैं चाहता हूँ।

SHRI B. K. HARIPRASAD (Karnataka): Mr. Vice-chairman, Sir, the people of Karnataka were the worst affected victims of the heavy rains and floods in two spells, rather in two instalments. The first spell was between the 11th and the 17th of June, and before they could recover from tis disastrous effects, the other spell befell them between the 8th and the 15th of July. I would like to thank the hon.

Prime Minister for having deputed one of his colleagues to assess the damage done to the rural parts of Karnataka, especially in the eight districts i.e. Belgaum, Chikmagalur, Dakshin Kannada, Dharwar, Hasan, Madugu, Shimoga and Uttara Kannada. A huge damage has been done to the public and private property. About 60 people have lost their lives and about 2,000 odd live stocks were destroyed. The State Government has taken some of the major relief work. Due to the financial constraint the work is very slow. They have requested the Centre to rush the relief, especially to restore the communication system, especially the roads. A lot of small bridges and dams have been damaged. I request the Government to rush the best possible relief to the State Government.

There was a request from the State Government for the supply of kerosene for the rural parts of Karnataka where, these floods and rains have caused havoc. I request the hon. Minister also to rush the much-needed kerosene to the State.

श्री बीरेन्द्र कश्यप (पंजाब)
मिस्टर वाइस चैयरमैन साहब आपका शुक्रिया पिछले साल भी जब फ्लड आये थे तो पंजाब में बहुत भारी नुकसान हुआ था और ऐसे फ्लड बहुत सालों के बाद आये थे और बंदाहाज आदमी भी मरे, मवेशी भी मरे सड़कों भी टूटी टेलीफोन सिस्टम बिल्कुल बर्बाद हो गया था, रेलवे सिस्टम बिल्कुल बर्बाद हो गया था। इसके अलावा फसलों को इतना नुकसान हुआ कि एक शेर है—मरते को मारे जाह मदान। अभी टेरोरिज्म के जखम से हम उबरे भी नहीं थे कि इस फ्लड ने लोगों को बिल्कुल तबाह और बर्बाद कर दिया। आज भी उस फ्लड का साया पंजाब के ऊपर है और कभी किसी इलाके में चले जाइये उनके निशान आज भी आपको मिलते हैं। उनकी तबाही जो हुई वहां की सड़कों की, फसलों की, लोगों की, वहां के भवैशियों को जो नुकसान पहुंचा आज तक उसका म्आवजा जितना सिजना चाहिए था उतना नहीं मिला।

भरकती सरकार ने जितना पैसा दिया था पंजाब के जखमों पर भरहुम लगाने के लिए वह बहुत कम था। इस बफा फिर पंजाब में फ्लड आये हैं। अमृतसर जिले में मुख्यासपुर जिले में बहुत से आदमी मारे गये हैं, फसलों को नुकसान हुआ है, बीमारी फैली हुई है मवेशी भी मारे गये हैं। इसके अलावा रोपड़ में कपूरथला में होशियारपुर में और दरिया के किनारे बंद का इलाका है वहां पर, फजिल्का के गांव हैं उनका खतरा बना हुआ है। दूसरे बांधों को भी आज खतरा का हुआ है। मैं आपकी बसंतत से सरकार से यह वखास्त करना चाहता हूं कि पंजाब का एक स्पेशल केस है क्योंकि हम 12 साल बर्बादी के दौर से गुजर कर आज तरक्की की मंजिल पर हैं। मैं सरकार से यह वखास्त करना कि फ्लड से मुक्त में आये हैं। जहां-जहां आये हैं उन लोगों की मदद करनी चाहिए लेकिन पंजाब का एक स्पेशल केस है। इस स्पेशल केस को देखते हुए पंजाब की हुरमत के लिए पंजाब को स्पेशल ग्रांट दीजिए।

श्री रामजी लाल (हरियाणा) :
उपसभाध्यक्ष महोदय अभी कटारिया जी कह रहे थे कि जब फ्लड आता है तो पंजाब का पानी हरियाणा में चला जाता है। घग्घर नदी जो हरियाणा में बहती है वह पंजाब से होती हुई फिर हरियाणा में आती है। आज हरियाणा के दतिया शहर और जाखल पानी से चारों तरफ से घिरे हुए हैं पानी उनके चारों तरफ घम गया है। सिरसा इलाके के पांच-सात गांव पानी में डूब गये हैं और वहां बड़ा भारी नुकसान हुआ है। ऐसा लगता है कि आने वाले हफ्ते में और भी ज्यादा फ्लड आयेगा और वहां और नुकसान होगा। हमारी सरकार ने इसके लिये प्रबन्ध किये थे लेकिन इस साल जितनी भारी बरसात हुई है एक दिन में 20-30 सेंटीमीटर बरसात हुई उसके कारण बहुत ज्यादा बाढ़ आयी है। यह बाढ़ ऐसा लगता है कि अब और ज्यादा नुकसान करेगी। आदरणीय मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया है उसमें उन्होंने यह कहा है कि 174 जिलों में बारिश अंदाजे से ज्यादा हुई है। कुदरत की बात तो समझ में नहीं आ सकती

लेकिन सरकार को इसके निम्न ज्यादा प्रबंध करने चाहिये। इसके लिये पहले न प्रबंध किया जाय। वह जान रही है कि बाढ़ के लिये जो रुपया स्टेट गवर्नमेंट्स को देने का वायदा किया जाता है वह पूरा रुपया समय पर उनके पास नहीं पहुंचता। यदि वह पूरा रुपया राज्य सरकारों के पास पहुंच जाय तो स्टेट गवर्नमेंट्स इसके लिये प्रबंध कर सकती है। लेकिन जब बाढ़ आती है तो ऐतान ज्यादा होता है और जब बाढ़ चली जाती है तो बाढ़ से ऐतान से कम क्षया पहुंचता है। इसलिए मैं आपके द्वारा सरकार में प्रार्थना करूंगा कि जब बाढ़ आती है तो बाढ़ आने से पहले इसके लिये पूरा प्रबंध करना चाहिये।

मंत्री जी ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि 18 जून को केंद्रीय सरकार ने राज्यों की बाढ़ की स्थिति की समीक्षा करने के लिये मीटिंग की है तो मैं सरक्षता हूँ कि उसमें उचित प्रबंध कर लिया होगा। लेकिन जो नुकसान है वह बहुत ज्यादा है। आपने जो राज्य के प्रतिनिधियों का सम्मेलन बुलाया था तो उसमें आपने कुछ आदेश भी दिये होंगे। उड़ीसा, बिहार, के पठार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिल और कश्मीर में इस साल रिफाई बरसात हुई है और हो भी रही है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि केंद्रीय सरकार ने अब तक क्या सहायता की है? जो राज्य सरकारों ने सहायता मांगी है क्या वह दे दी गयी है या नहीं? किन किन राज्यों में कितनी कितनी आवश्यक वस्तुएँ, दवाइयाँ और अन्य सामग्री भेजी गयी है यह मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ?

सेना, वायुसेना और नौसेना ने ऐसे कितने फंसे हुए लोगों को पानी से निकाला और कितने भोजन के पैकेट गिराये? क्या वह सभी वस्तुएँ पहुंचायी गई हैं? क्या वहाँ बीमारों के लिये दवाइयाँ पहुंच रही हैं? सभी पीड़ितों के लिये दवायें पूरी तरह से पहुंचा दी गई हैं? कितने लोगों को वहाँ से निकाला गया है और कितने खाने के पैकेट और दवाइयाँ पहुंचाई

गई हैं? क्या आपने इन सब बातों का पता लगा लिया है? क्या वहाँ कोई भूखा तो नहीं रह रहा है या दवाइयों के बिना पीड़ित तो नहीं है, मैं इन्हीं बातों का स्पष्टीकरण आपके माध्यम से चाहता हूँ।

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश): माननीय उपमहाध्वज जी, प्रायः प्रतिवर्ष हम लोग बाढ़ और सूखे के प्रकार से जो जान-माल की हानि होती है, न केवल उस पर चर्चा करते हैं बल्कि अकसोस भी प्रकट करते हैं और सरकार ने हमें यह आश्वासन मिलता है कि हम लोग निश्चित रूप से कोई ऐसी योजना बनायें जिससे हमारे देशवासी इन प्रकोपों से प्रभावित न हों। लेकिन हर साल बाढ़ से प्रभावित लोगों के बारे में यहाँ पर जो वक्तव्य दिया जाता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं।

महोदय, इसका दुर्भाग्यजनक पक्ष यह है कि आज फिर हम लोग बाढ़ से जो जान-माल की हानि हुई है, उस वक्तव्य पर चर्चा कर रहे हैं। मैं अपने आपका, मध्य प्रदेश में आने की वजह से, केवल मध्य प्रदेश तक सीमित रखना चाहूँगा। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश के लगभग 15 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं जिसकी वजह से लगभग साढ़े तीन लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। और लगभग 1849 गांवों में बाढ़ आई जिसकी वजह से 36 लोग मारे गये और जो घरों का नुकसान हुआ, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 23140 घर बरबाद हो गये। इसके अतिरिक्त जो पशुओं की हानि हुई वह करीब 1911 के करीब आंकी गई। यह जो सरकारी आंकड़े थे लेकिन इससे भी ज्यादा हानि हुई है, ऐसा वहाँ के प्रत्यक्षदर्शी लोगों का अनुमान है। माननीय मंत्री जी कृपापूर्वक उन स्थानों पर गये, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ से जहाँ बहुत ज्यादा भयानक बाढ़ आई वहाँ उन्होंने खुद अपनी आंखों से जा कर हाल देखा और निर्देश दिये हैं कि बाढ़ पीड़ितों को सहायता मुहैया कराई जाए, उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। आगरा और इलाहाबाद से विमान आए उन्होंने बाढ़ में जो लगभग 158 लोग फँस गये थे उनको निकाला और लगभग 30 हजार खाने के पैकेट बाँटे

१० : यह सरकारों ने यह किया गया
राम है । इसके प्रतिरिक्त बालेदरी
मार्ग-निर्देशन, योजना आदि-इत्यादि ने भी
मन्द की है । महत्वपूर्ण पहल यह है कि
यह जो जानमान की हानि हुई है यह तो
शुकी गई लेकिन उसके प्रतिरिक्त रोड
बराबाद हो गये, केनाल बराबाद हो गई,
उनके बारे में हम लोगों ने कोई भी
विचार नहीं किया है । उस हानि को हम
लोग कैसे पूरा करेंगे ? जो स्वास्थ्य सेवाएं
मुहैया कराई जानी चाहियें थी, जो बाढ़
आने की वजह से लोगों को तरह तरह की
बीमारियां हुई, उसके आउटर इफट्स अभी
भी हो रहे हैं । वहां प्यास दवाइयां नहीं
हैं इसलिए यह आवश्यक है कि केन्द्रीय
सरकार की तरफ से पहल की जानी
चाहिये । यहां से एक मेडिकल स्पेशलिस्ट्स
की टीम जाए और भारी दवाइयां यहां से
मुहैया कराई जाएं । वहां पर दवाइयों की
सख्त कमी आ गई है । जितनी मांग
मध्य प्रदेश सरकार ने की है, वह वित्तीय
मदद भी उनकी दी जाए । मध्य प्रदेश
बहुत बुरे तरीके से प्रभावित हुआ है ।
अभी तक केवल 14 करोड़ रुपये बाढ़
नोडितों के लिए केन्द्रीय सरकार को तरफ
से दिये गये हैं और केवल दो इंस्टालमेंट्स
दी गई हैं । मेरा आग्रह माध्यम से केन्द्र
सरकार से प्रनुरोध है और विशेष रूप से
हमारे कृषि राज्य मंत्री जी से जो न केवल
मध्य प्रदेश में आते हैं बल्कि उस क्षेत्र
का प्रतिनिधित्व करते हैं उत्तरीसगढ़ क्षेत्र में
बाढ़ से लोग बहुत बुरे तरीके से प्रभावित
हुए हैं, इसलिए निश्चित रूप से मैं केन्द्रीय
सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि वह
राशि उपलब्ध कराई जाए जो मध्य प्रदेश
सरकार ने 650 करोड़ रुपये की मांग की
है । इसके अतिरिक्त जो सुविधाएँ मध्य
प्रदेश सरकार ने मांगी हैं वह सारी सुवि-
धाएँ केन्द्र सरकार से उपलब्ध कराई
जानी चाहिए । यह तो रही मध्य प्रदेश
सरकार के सर्वर्ष में बात लेकिन मैं इससे
आगे बढ़ कर के बात निवेदन करना
चाहूंगा कि सरकार अपनी तरफ से ऐसी
दूरगामी योजना बनाए कि हमारे देशवासी
बाढ़ और सूखे के प्रकोप से प्रभावित न
हो सकें । इसके अतिरिक्त निश्चित
रूप से हमें ऐसी कोई धार्मिक करना
बहुत आवश्यक है, केवल मौसम

विज्ञान का सहारा लेकर हम नहीं चल सकते हैं, केवल इस बात का ही इस्तेमाल कर के हम सर्वोपरि प्रकट नहीं कर सकते कि विभिन्न सतहों पर हम लोगों के अलग-अलग लेवल के अधिकारियों और मंत्रियों को बैठक बुलाई जिसमें यह निर्णय लिए गए। प्रश्न यह है कि उन बैठक के बाद लोग वापस तो प्रभावित होने से मुक्ति पा सके या नहीं, यह महत्वपूर्ण बात है। इसलिए निश्चित रूप से इस निष्कर्ष पर पहुँचना आवश्यक है कि हमारे देशवासियों इस प्रकार के प्रकोपों से मुक्ति पा सकें।

SHRI H. HANUMANTHAPPA: Thank you, Mr. Vice-Chairman, for giving me this opportunity to draw the attention of the House to some of the important issues. Actually, before I start, I thank the Prime Minister for sending his emissaries to the flood-affected areas to have first-hand information. But, Sir, the emissaries have come back. The first hand information has been brought to Delhi. The emissaries have satisfied themselves about the damage and the loss that has occurred on the spot. They have made statements' at the State head-quarters stating, "Yes, we are satisfied that this much is the loss." When the Prime Minister's emissaries have said that are they satisfied about the damage, when they made an announcement that this was the loss, what is the follow-up action? Nothing. This questions the very credibility of our system and of our functioning. I want to draw the attention of the Minister to the seriousness that the Prime Minister attached to this subject, the seriousness with which the Prime Minister sent his personal emissaries to go to the flood-affected areas and bring the report. If that seriousness is not shown subsequently either by the Ministry of Agriculture or by the Agriculture Department, then, with due respect, I submit that there is something wrong somewhere. Sir, every year, there are floods. This time Karnataka has submitted a memorandum. For the last

two years, we have been submitting memoranda but not a single pei has been given to the State as relief. What is this? How do you satisfy the people? There are floods, there are calamities, there are losses and there are damages. Your team goes to the affected States, brings the report but nothing happens thereafter. I request the Minister to see to this aspect. By simply coming with the statement and by making the clarifications, the matter does not end. Something has to be done further. If we take shelter under the Calamity Relief Fund fixed by the Eighth Finance Commission and say that the Tenth Finance Commission is looking into it, without realising as to what the real position is, that would not help us. Has the Ministry made its recommendations depending on the realities? If it has been decided that 25 per cent of the amount has to be spent by the State and 75 per cent has to be given by the Centre, then why doesn't the Government accept the same norms as are fixed by the Eighth Finance Commission and allow the State Government to spend that much and get that money reimbursed? I do not know what the hitch is. Actually, the Finance Minister was present in the House I wanted the Finance Minister to be present here when I speak so that he can throw some light on these things. Unfortunately, he left the House. The point is, the Eighth Finance Commission has fixed certain criteria according to which 25 per cent expenditure is to be borne by the States and 75 per cent expenditure is to be borne by the Centre. But if the damages are more what should we do? Today, the damage is around Rs. 100 crores. When it is so, let us apply the same formula that 25 per cent expenditure would be borne by the State and 75 per cent expenditure would be borne by the Centre. Why don't you follow this formula? Why don't you allow the States to incur the necessary expenditure so that relief reaches the people in time and then you can reimburse the money? Why don't you give that clearance?

What is the hitch? If there is some hitch, the Ministry concerned, the Planning Commission and the Finance Ministry should remove that hitch among themselves but the people should not suffer. If the people are in distress and if we do not give them the relief in time, it is of no use because justice delayed is justice denied. If it does not reach them in their distress, then it is of no use. It is no use of discussing it in Parliament by making statements or by giving clarifications. I request you to look into the ground reality. Though so many States suffered from floods, only the State of Gujarat got Rs. 50 lakhs because that news was published in the Press. From this, it appears that no other State suffered from floods. How is it that only the State of Gujarat suffered from floods and no other State suffered from it? The floods in the other States were not taken note of. This is not the way of going ahead with it. If the other States do not attract so much attention, at least, you could have sent Rs. 10 lakhs, Rs. 20 lakhs or Rs. 30 lakhs so that the people of those States might feel that there is a Government which is concerned about their distress. But that has not happened. Sir, I have already told you that the Eighth Finance Commission has not set the criteria or norms for the Calamity Relief Fund. The damages caused by the wrong" calculated. This should be peeressed taking into account the realities out there should be certain norms fixed for it. If there is a ratio of 25:75, that ratio should be nrolied to the damages caused. It should not be a fixed amount. If a limit of Rs. 27 crores is fixed, can we ask Nature to limit its calamity or flood damages within Rs. 27 corps? This is what is happening! If the Agriculture Minister comes and says, "You have got a Calamity Relief Fund, the riehfh Finance Commission has fixed your allocation, this is the limit, you cannot go beyond that and the Tenth Finance Commission is looking into that", till then do we have to order the flood or

the drought situation not to cross the limit, the *Laxman rekha* of Rs. 27 crores in Karnataka or Rs. 35 crores in Madhya Pradesh or Rs. 17 crores in Assam? This will not serve the purpose. So, I request the Agriculture Ministry that it should be practical and should go before the Finance Commission or the Planning Commission to say that the realities are different, our norms are different. First, scrap the norms. If the Agriculture Minister himself goes to Gujarat and sees the damages caused by the calamity, he would be able to say, "Yes, this should be reimbursed." If the Minister of State for Agriculture goes to Madhya Pradesh and sees the damages, he would be able to give more relief. And then, the people of that State would say, "Yes, the Minister has come. We will get some relief."

Sir, if there are certain norms left over, they should also be included. The crops lost is not included. Some houses have collapsed. Some bridges have collapsed. Bridges and tanks and all other things, you have fixed these within that limit. When there is a unlimited damage—and you are also convinced of it—I only request the Agriculture Ministry that it should be practical. Every year we are discussing; every year we are getting the reply, "There is a Calamity Relief Fund established by the Finance Commission." So, if you cannot order Nature to limit its damages within that Calamity Relief Fund, Sir, you have to change your norms, you have to fight with the Finance Commission and the Planning Commission to get more relief.

And, lastly, I want one more piece of information. What is the demand made by these States? What is the damage caused by the calamity in each State? What is the demand made by them and what is the amount sanctioned by you? That shows the concern of all, the reality and the approach adopted by us. If there is a wide gap, the people of this country will look towards Delhi with high hopes. We have to keep our promises and fulfil the expectations and aspirations of the people.

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अरविन्द नेतानम) : उपसभाध्यक्ष महोदय, वर्षाकालीन सत्र में इस देश में अधिकतर बाढ़ की चर्चा हम लोग करते हैं और कभी-कभी बाढ़ और सूखा पर भी चर्चा करते हैं, यह बात सही है और जैसा कि पिछले हफ्ते इस सदन में बयान दिया गया था पूरे देश में जो बाढ़ की स्थिति है उस पर और उस पर आधारित माननीय सदस्यों ने कुछ स्पष्टीकरण चाहा है। इस बार जो जुलाई के महीने में करीब-करीब जो बारिश इस देश में हुई है उससे 12,601 गांव पूरे देश में प्रभावित हुए और करीब सवा सात लाख हेक्टेयर जमीन, कृषि जमीन प्रभावित हुई है, उसमें 54 लाख आबादी 5 लाख हेक्टेयर करीब की जो कृषि की उपज भी काफी डैमेज हुआ है, करीब 1.64 लाख हाउस डैमेज हुए हैं, ह्यूमैन लाईफ लॉस करीब 567 है, कैटल डैडज लॉस 21542 है। इस प्रकार से काफी राज्यों में जो डैमेज हुए हैं वे काफी गंभीर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है और इस संबंध में मुख्य बयान में भी बताया गया है।

महोदय, मैं सबसे पहले माननीय हनुमन्तलप्पा साहब के प्रश्न पर आना चाहूंगा। माननीय हनुमन्तलप्पा जी का मूल प्रश्न कैलेमिटी रिलीफ फंड का है। महोदय, नीचा वित्त आयोग सभी राज्यों की राय से इस निर्णय पर पहुंचा कि कैलेमिटी रिलीफ फंड का स्वरूप क्या होना चाहिए और हर राज्य के लिए एक फार्मूला हो गया कि कैलेमिटी रिलीफ फंड हर राज्यों के अलग-अलग है। उसी के मुताबिक जब कभी भी ऐसे मौके आते हैं तो उसी की लिमिट के अंदर हम राज्य सरकारों को मदद करते हैं। यह बात नौवें फायनेंस कमिशन में तय हुई है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि राज्य इस नेचुरल कैलेमिटी से प्रभावित नहीं होते तब भी राज्यों को केन्द्र से सहायता मिलती है। यह एक फिक्स फार्मूला है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि बहुत ज्यादा डैमेज होता है, पर फार्मूले के हिसाब से मदद कम मिलती है। पर जो एक स्टैंडर्ड फार्मूला फिक्स हो गया है, उसमें मेरे लिए दिक्कत यह है कि मैं उस फार्मूले के बाहर नहीं जा सकता। माननीय सदस्य ने बिल्कुल ठीक

कहा है, पर अब न कि दमना वित्त आयोग है और उसमें सभी राज्य सरकार इस फ़ॉर्मूले को तय करेंगी कि इस फ़ॉर्मूले को किस स्तर से रद्दो-बदल करना है। प्लानिंग कमिशन और फाइनेंस मिनिसट्री जो भी तय करेंगी, उसके मानना पड़ेगा और हम भी चाहेंगे कि अगर राज्य सरकारों को इसमें कोई दिक्कत है तो निश्चित है कि उनका तरफ से सब दसवें वित्त आयोग के सामने मुझसे आएगा और जो प्रजेंट कैलिमिटी रिलीफ फंड की स्थिति है, उसमें कहीं-कहीं रद्दो-बदल होगा, ऐसा मैं मानकर चलना हूँ। तो माननीय : वनतप्प जी का जो मूल प्रश्न है...

SHRI H. HANUMANTHAPPA: We accept the formula. All the States will accept the formula. I am only requesting the Agriculture Minister, let us go by the formula. The formula is 25 per cent from the State and 75 per cent from, the Centre. Let us accept that. But the limit is the bottleneck, i.e. that the calamity should be within Rs. 27 crores or Rs. 35 crores. We accept the formula. Let us go by the formula. But when the damage is more than the limit we cannot talk on the basis of the same formula. Will the Agriculture Ministry accept this formula and go before the Finance Commission? We have seen that the damages are much more than the limit. We cannot ask of flood or of drought to limit the damage within the formula.

SHRI ARVIND NETAM: This is not a question of my Ministry. This is a question of all States, the Planning Commission and the Finance Ministry. They will decide the formula. That is the point.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: We agree to the formula.

THE VICE-CHAIRMAN (SYED IBTEY RAZI): Yes, you proceed.

श्री अरविन्द नेताम : उपसभाध्यक्ष जी, बहुत-सी बातें माननीय सदस्यों ने कहीं। करीब-करीब सभी राज्यों को कैलिमिटी

रिलीफ फंड में मदद दी गई है। उनके हिस्से के अनुसार भारत सरकार से मदद दी गई है। उसमें बहुत-से राज्यों को तोमरों किस्त है, बहुत-से राज्यों को चौथा किस्त है। चार किस्तों में कैलिमिटी रिलीफ फंड का बांटा जाता है और बहुत-से राज्यों को सारी किस्त दे दी गई है। कुछ राज्यों की एक किस्त बाकी है। अगर कोई राज्य मांगेगा तो हमें चौथा किस्त देने में कोई एतराज नहीं है।

श्री सुरेश पचोरी : मंत्री जी, नव्य प्रदेश के बारे में बताइए।

श्री अरविन्द नेताम : सभी राज्यों की इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, पर चाहें तो सभा पटल पर पूरी इन्फॉर्मेशन रख दूंगा। उसमें कोई दिक्कत नहीं है।

रामचन्द्रन साहब ने एक प्रश्न किया रिवालिफ फंड का।

My answer is that we have got this 'Calamity Relief Fund. With this system you get immediate relief from the Centre if any calamity occurs.

SHRI S. K. T. RAMACHANDRAN: I am not talking about the relief fund which you are talking. Sometimes the magnitude of the calamity is so big that you cannot meet the demands within the gamut of the budget. Last year, I suggested generation or constitution of a revolving fund. If you have funds in reserve, at the time of calamity you can immediately rush fund for relief and rescue operations.

SHRI ARVIND NETAM: This is the kind of arrangement which the Government makes through the Calamity Relief Fund. As I said, there will be changes in the structure of the Calamity Relief Fund. Certainly, there will be a change.

उपसभाध्यक्ष महोदय, यह जो मेट्रोला-जिकल डिपार्टमेंट के बारे में, जो मानसून के बारे में उन्होंने कहा, इस संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि यह जो इंडियन मेट्रोला-जिकल डिपार्टमेंट है, मानसून के बारे में

पूरी इन्फार्मेशन रखता है और स्वेस वार्निंग के लिए एडवॉस में पूरी इन्फार्मेशन देता है और यह पूरी जानकारी रखता है और धीरे-धीरे इस डिपार्टमेंट में काफी तरक्की हुई है इसमें कोई दो राय नहीं है और इस विषय से जो सूचनाएँ देश में भिज रही हैं वे काफी सही भिज रही हैं। परन्तु इस बात जैसा कि आप जानते हैं कि जुलाई के माह में जो इस डंग में बारिश हुई है ऐसी बारिश हुई है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा स्थिति में क्षति होना स्वाभाविक है।

मोना साहब ने भी वृहन में राज्यों खास कर के बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा आदि में बीमारियों के बारे में, दवाओं की समस्या के बारे में कहा। जिन राज्यों में ये समस्याएँ हैं, उनके बारे में हमारे निमित्तों में जो कमेटी बनी है रिलीफ कमिशनर की चेयरमैनशिप में, हम मानिटरिंग करते हैं, सैन्य अलार्म बना है जिसमें हम 24 घंटे मानिटरिंग करने रहते हैं और हम बात की कोशिश करते रहते हैं कि जहाँ-जहाँ बाढ़ आई है वहाँ खास कर बीमारियों के बारे में हम निगरानी रखते हैं कि बाढ़ के बाद बीमारी तो नहीं है। बीमारों अगर हैं तो उन संबंध में कोई निष्कर्ष तो नहीं है। परन्तु मुझे यह बातें में खुशी हो रही है कि जैसे कोई राज्य सरकार नहीं है जिसने बीमारी के बारे में अपनी अमर्त्यता आहिर की हो और वह कंट्रोल से बाहर हो। वैसे भी राहत के बारे में सभी राज्य सरकारों से हमारा निरंतर सम्पर्क बना हुआ है। इस संबंध में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इस बार माननीय प्रधान मंत्री जी ने विशेष रुचि लेकर के, जैसा कि माननीय सदस्यों, ने कहा, अलग से केन्द्रीय मंत्रियों को राज्यों में भेजा और खास कर के वहाँ से रिपोर्टें मंगाई और स्वयं इस बात में रुचि लेकर के कि क्या नुकसान हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, उस बात की जानकारी ली। यह हम बात का चोटक है कि प्रधान मंत्री जी ऐसे कठिन समय में स्वयं कितना ध्यान रख रहे हैं। मंत्रियों को भेजकर के, रिपोर्टें मंगाकर के जो भी हो सकता है भारत सरकार आगे आने वाले समय में इस संबंध में जो भी मदद कर

सकती है, उस पर कुछ न कुछ जरूर विचार करेगी।

कर्नाटक के हमारे माननीय सदस्य ने केरोसीन के बारे में कहा, 3,000 किलोमीटर केरोसीन आयन हमने रिलीज किया है और करीब-करीब 5 करोड़ रुपया केनेमिटी रिलीफफंड में हमने रिलीज किया है।

मध्य प्रदेश के बारे में माननीय पत्नीरौ जी ने कहा कि हमने एक किस्त तो रिलीज कर दी, दूसरी किस्त हमने रिलीज तो कर दी पर आई नहीं है, इस बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि वह दूसरी किस्त भी वित्त मंत्रालय से बहुत जल्दी ही रिलीज हो जाएगी। क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने दोनों किस्त एक साथ मांगी थी, इसलिए हम दोनों किस्त एक साथ कर रहे हैं, पर एक के बाद एक कर रहे हैं, जैसी कि प्रक्रिया है। हालांकि मध्य प्रदेश ने करीब-करीब 200 करोड़ रुपया मांगा है पूरा क्षति का... परन्तु जो कैलेमिटी रिलीफ फंड से पैसा मंगा है, एक बार हमने 6 करोड़ रिलीज किया है, फिर 6 करोड़ रुपया रिलीज करने वाले हैं, यह फाइनल कमीशन में पड़ा हुआ है, आशा है जल्दी हो जाएगा। इस प्रकार से जो भी पैसा हम भेजे हैं उनमें से सभी राज्यों को हम दे रहे हैं और जो राज्य पूरी किस्त की मांग कर रहे हैं, उन को पूरी किस्त दे रहे हैं। इस प्रकार से जो भी अभी वर्तमान समय में व्यवस्था है उस व्यवस्था के तहत हम इस बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकारों को मदद कर रहे हैं और इस बार सौभाग्य से मंत्रालय की तरफ से जो भी व्यवस्था थी, राज्य सरकारों के साथ कोऑर्डिनेशन से काम बहुत अच्छा हुआ है और हो रहा है। जो परिस्थितियों को संभालने में राज्य सरकारों का सहयोग मिला है उस के लिए मैं राज्य सरकारों को धन्यवाद देता हूँ। उन के सहयोग से हमने जो सफलता प्राप्त की है उस से ज्यादा जन और धन की क्षति नहीं हुई है। यह इस बात का चोटक है कि राज्य सरकारों ने मुस्तीदी से काम किया है और बहुत सी राज्य सरकारों ने बहुत अच्छा काम किया है।

श्रीमान्, भारतीय सदस्यों ने जो प्रश्न उठाए हैं उनका जवाब देने की मैंने पूरी कोशिश की है और जो भी इफॉर्मेशन, होगा, जैसा कि मैंने कहा है, पूरे राज्यों को कितना कितना दिया है, वह सभा-घटन पर रख दी जाएगी।

SHRI K. RAHMAN KHAN: Sir, the demand from the Karnataka Government! is for about Rs. 100 crores and the hon. Minister has mentioned that Rs. 5 crores have been released. Is it sufficient to meet the calamities?

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI): I think the hon. Minister has explained the whole case. I don't think it is possible for him to reply in

response to each State individually. He has explained what the Government has done under the Calamities Relief Fund... (Interruptions) Mr. Minister, would you like to say something?

SHRI ARVIND NETAM: Mr. Vice-Chairman, Sir, as I said, we have limitations under the Calamities Relief Fund. I adjourned till 11 A.M. tomorrow.

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI): The House stands adjourned till 11 A.M. tomorrow.

The House then adjourned at fifty-three minutes past five of the clock till eleven of the clock on 3rd August, 1994.